

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

28}

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2010/पौष 29, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2010/PAUSA 29, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 जनवरी, 2010

सं. टीएएमपी/53/2008-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतदृद्वारा संलग्न आदेशानुसार, जेएनपीटी और मुम्बई के बीच संचलित पोतांतरण कंटेनरों के लिए दरों पर स्पष्टीकरण माँगने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त संदर्भ का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/53/2008-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

आवेरक

आदेश

(दिसम्बर, 2009 के 30वें दिन पारित)

यह मामला जेएनपीटी और मुम्बई पत्तन के बीच संचलित पोतांतरण कंटेनरों के लिए दरों पर स्पष्टीकरण माँगने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त संदर्भ से संबंधित है ।

- जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 2008 द्वारा जेएनपीटी और मुम्बई पत्तन के बीच संचलित पोतांतरण कंटेनरों के बिल तैयार करने के संबंध में मेरीटाइम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एमएसपीएल) द्वारा जेएनपीटी को दिया गया संदर्भ अग्रेषित किया है। एमएसपीएल द्वारा अपने संदर्भित पत्र में कही गई प्रमुख बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:--
 - आयात कंटेनर बार्जों के माध्यम से जेएनपीटी से मुम्बई पत्तन पोतांतरित किए जाते हैं। (i).
 - जेएनपीटी के दरमान (एसओआर) की टिप्पणी 4 में कहा गया है कि तटीय नौचालन पर भारतीय पत्तन को (ii). अनुवर्ती पोतांतरण अथवा विलोमतः के लिए जेएनपीटी में उत्तरने वाले विदेशी पत्तन के कंटेनर से विदेशी पोतों के लिए निर्धारित पोतांतरण प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल किया जाएगा और उसका 50 प्रतिशत तटीय श्रेणी के लिए
 - चूंकि जेएनपीटी एसओआर पोतांतरण कंटेनरों के लिए तटीय प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है, इसलिए यह अनुमान (iii). लगाया गया है कि विदेशी प्रशुल्क लागू होगा।
 - 20' पोतांतरण कंटेनर के लिए, जेएनपीटी एसओआर में निर्धारित दर रु० 2550/— है। इसलिए, टीपी बिलिंग रु० (iv), 1275/— पर अथवा विदेशी पोत के लिए रू० 1275/— के आधार पर और तटीय बार्ज के लिए रू० 637.50 पर
- उपर्युक्त संदर्भ में, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 2008 में निर्धारित निवेदन किए हैं:--2.2.
 - तटीय पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए कोई पृथक दर निर्धारित नहीं है। (i).
 - पोतांतरण कंटेनरों के लिए लागू प्रभार सामान्य प्रहस्तन प्रभारों का 50 प्रतिशत है। (ii).
 - जेएनपीटी इस सेवा के लिए जेएनपीटी दरमान के अध्याय 3 के खंड 3.3.1 (घ) के अनुसार रू० 2550/- प्रति (111).
- चूंकि एमएसपीएल जेएनपीटी के मतों से सहमत नहीं है, इसलिए जेएनपीटी ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि 2.3. पोतांतरण कंटेनर के लिए पत्तन द्वारा प्रभार्य वास्तविक प्रभारों के साथ-साथ उसके दरमान के प्रावधानों को स्पष्ट करें।
- निर्धारित परामशीं प्रक्रिया के अनुसार, जेएनपीटी से संलग्नकों के साथ प्राप्त संदर्भ की प्रति संबद्ध उपयोक्ताओं / उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी।
- मुम्बई और न्हावा शेवा शिप एजेंट्स असोसिएशन (मानसा) और कंटेनर शिपिंग लाइन्स असोसिएशन (इंडिया) [सीएसएलए] से प्राप्त टिप्पणियां जेएनपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक हमें
- इस मामले में संयुक्त सुनवाई 27 नवम्बर 2009 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी।
- इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग-से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए
- इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:--
 - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेश के (i). अनुपालन में, सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर निजी टर्मिनल प्रचालकों पर प्रभार्य तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोत संबंधित प्रभारों के लिए रियायती दरें निर्धारित करने के लिए, इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी / 4 / 2004 – सामान्य दिनांक 10 जनवरी 2005 द्वारा 1 फरवरी 2005 से स्तमान्य शर्तों के रूप में सरकार का नीति निदेश शामिल करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों के दरमान संशोधित किए थे। तत्संबंधी पत्तनों / टर्मिनलों के दरमान में सरकार के नीति निदेश के अनुसार रियायती तटीय कार्गों / कंटेनर / पोत संबंधित प्रभार निर्धारित करने के लिए सामान्य शर्ते शामिल की गई थीं।
 - मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 4.3 तटीय कंटेनरों के लिए सामान्य कंटेनर संबंधित प्रभारों की दरों के (ii). 60 प्रतिशत से अनाधिक रियायती प्रशुल्क निर्धारित करता है।

- प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 5.5.1 विनिर्दिष्ट करता है कि पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रहस्तन प्रभार रियायती होंगे। ऐसे प्रभार तटीय कंटेनरों के लिए खंड 4.3 में निर्दिष्ट रियायत के अधीन लागू प्रहस्तन प्रभारों के संदर्भ में (iii). परिकलित किए जाएंगे।
- जेएनपीटी का दरमान पिछली बार सितम्बर 2006 में मामला सं. टीएएमपी / 48 / 2005--जेएनपीटी में आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2006 द्वारा संशोधित किया गया था। जेएनपीटी के मौजूदा दरमान के अध्याय 1 में निर्धारित खंड 1.2 (iv). (vi) (ख) विदेशी कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए निर्धारित दरों के 60 प्रतिशत पर तटीय दरों की वसूली के लिए दिया गया है।
- जेएनपीटी के दरमान में निर्धारित खंड 3.3.3 की टिप्पणी 4 के अनुसार, तटीय नौचालन पर भारतीय पत्तन अथवा विलोमतः अनुवर्ती पोतांतरण के लिए जेएनपीटी में उतरने वाले विदेशी पत्तन के कंटेनर से विदेशगामी पोतों के (V). लिए निर्धारित पोतांतरण प्रभारों का 50 प्रतिशत और तटीय श्रेणी के लिए उस निर्धारित का 50 प्रतिशत वस्ल किया जाएगा।
- पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों की वसूली के संबंध में जेएनपीटी के मौजूदा दरमान के खंड 3.3.1 (vi). में किया गया निर्धारण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति टीईयू (रु० में) विदेशी कंटेनर		
92. VI.	144	लदा हुआ	खाली	
1	1 – 3000 टीईयू	2550	2210	
·	3001 - 6000 टीईयू	2380	2040	
<u> </u>		2210	1870	
3.	6001 - 9000 टीईयू	2040	1700	
4.	उसके पश्चात	2040	77.00	

- एक दरमान सिर्फ उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए कुछ दरों का सैट देते हुए एक दस्तावेज नहीं है। इसमें दरों के क्रियान्वयन को शासित करने वाली शर्तें भी होती हैं। इसलिए, जेएनपीटी का दरमान निष्कर्षतः लागू प्रशुलक पर निर्णय लेने के रूप में देखा जाना चाहिए। जेएनपीटी के मौजूदा दरमान में निर्धारित अध्याय 1 का खंड 1.2 (vi) (ख) और खंड 3.3.3 की टिप्पणी 4 साथ-साथ पढ़ने से यह स्थिति निकलकर आती है कि पोतांतरण कंटेनरों के लिए तटीय दरें लागू हैं और दरमान में दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रभार निर्घारित करने वाली तालिका सिर्फ विदेशी कंटेनरों के लिए है जो तालिका में दिए गए शीर्षक से देखा जा सकता है। यदि तटीय पोतांतरण के लिए कोई रियायत देने की मंशा न होती, जो किसी भी मामले में सरकारी निदेश के प्रतिकूल होगा, तो तब जब पोतांतरण में विदेशी के साथ-साथ तटीय लैग्स भी शामिल हैं, प्रभार वसूल करने के आघार का ब्योरा देते हुए खंड 3.3.3 के अधीन टिप्पणी 4 निर्धारित करने की जरूरत नहीं होती।
- संयोगवश, जेएनपीटी में अन्य दो निजी कंटेनर टर्मिनलों नामतः एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के दरमान में, पोतांतरण कंटनरों के लिए तटीय दरें विदेशी पोतांतरण कंटेनरों के लिए निर्धारित दरों के 60 प्रतिशत पर निर्धारित (viii). की गई है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल ने शुरू में जेएनपीटी का प्रश्लक ढाँचा अंगीकृत किया था और एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल का मौजूदा प्रशुल्क ढाँचा जेएनपीटी के उसी प्रशुल्क ढाँचे से ज्यादा आकर्षित लगता है। एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल दोनों के दरमान में तटीय कटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों से संबंधित पृथक प्राक्धान किया गया है जोकि विदेशी पोतांतरण कंटेनरों के लिए निर्धारित दरों के 60 प्रतिशत के समकक्ष है।
- पहले उल्लिखित जेएनपीटी के दरमान के खंड 1.2 (vi) (ख) का अनुसरण करते हुए और 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 को ध्यान में रखते हुए जिसमें तटीय पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रहस्तन प्रभारों का (ix). निर्धारण विनिर्दिष्ट करता है, खंड 3.3.1 में मौजूदा उप-खंड घ के अधीन अनुसूची को निम्नवत् पढ़ने के लिए लिया जा सकता है:-

घोतांतरण कंटेनरों का प्रहस्तनः

क्र.सं.	व कंटेनरों का प्रहस्तनः विवरण	दर प्रति टीईयू (रू० में)			
		विदेशी कंटेनर		तटीय कंटेनर	
		लदा	खाली	लदा हुआ	खाली
		हुआ			1000
1	1-3000 टीईयू	2550	2210	1530	1326
1.		2380	2040	1428	1224
2.	3001-6000 टीईयू	2210	1870	1326	1122
3.	6001-9000 टीईयू			1224	1020
4.	उसके पश्चात	2040	1700	1224	1020

- खंड 3.3.3 की मौजूदा टिप्पणी 4 के अनुसार, तटीय नौचालन पर भारतीय पत्तन को अथवा विलोमतः अनुवर्ती पोतांतरण के लिए जेएनपीटी में उतरने वाले विदेशी पत्तन के कंटेनर से विदेशी कंटेनरों के लिए निर्धारित पोतांतरण प्रभारों का 50 प्रतिशत और तटीय श्रेणी के लिए उस निर्धारित का 50 प्रतिशत वसूल किया जाएगा।
- परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि जेएनपीटी का मौजूदा दरमान तटीय कंटेनरों के पोतांतरण के लिए रियायती दरों हेतु पहले ही दिया गया है और लागू दरें डिवाइजिंग करने के लिए दिया गया है जब पोतांतरण में विदेशी लैग और तटीय संचलन शामिल है। जेएनपीटी को अपने दरमान में दिए गए
- इस प्राधिकरण का यह मतह है कि जेएनपीटी से इतर किसी अन्य पत्तन के लिए घोषित अंतिम गंतव्य के साथ विदेशी पत्तन का जो कंटेनर बीच मार्ग में जेएनपीटी में प्रहस्तित किया जाता है केवल वही पोतांतरण दरों के लिए पात्र होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक विदेशी कंटेनर जो मूलतः जेएनपीटी में ले जाया जाता है और बाद में जेएनपीटी से दूसरे भारतीय पत्तन को पुनः परेषित किया जाता है तो वह पोतांतरण दरों के लिए पात्र नहीं होगा। जेएनपीटी से दूसरे भारतीय पत्तन तक पुनः परेषण के ऐसे मामलों में, जेएनपीटी और दूसरे पत्तन के बीच इसके तटीय नौचालन के लिए सामान्य तटीय दर लागू की जाएगी। चूंकि यह मुद्दा सरकार की तटीय नीति से जुड़ा हुआ है. इसलिए इस उप-अनुच्छेद में प्रतिवेदित इस प्राधिकरण का निवर्चन पोत परिवहन मंत्रालय

रानी जाधव. अध्यक्षा

Applicant

[विज्ञापन [[]/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 12th Junuary, 2010

No. TAMP/53/2008-JNPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the reference received from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) seeking clarification on the rates for the transhipment containers moved between JNPT and Mumbai Port as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/53/2008-JNPT

The Jawaharlal Nehru Port Trust

ORDER

(Passed on this 30th day of December, 2009)

This case deals with a reference received from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) seeking clarifications on the rates for transhipment containers moved between JNPT and

- The JNPT vide its letter dated 3 March 2008 has forwarded a reference made by Maritime Service Private Limited (MSPL) to JNPT regarding billing of transshipment containers moved between JNPT and Mumbai port. The main points made by MSPL in its letter in reference
 - The Import containers are transhipped from JNPT to Mumbai via Barges. (i).
 - Note 4 of the JNPT Scale of Rates (SOR) states that a container from foreign port landing at the JNPT for subsequent transhipment to an Indian Port on a coastal voyage or vice versa would be charged at 50% of the transhipment charges prescribed for foreign vessels and 50% of that prescribed for coastal category.
 - Since the JNPT SOR does not prescribe coastal tariff for transhipment containers, (iii). it is assumed that the foreign tariff will apply.
 - For a 20' transhipment container, the rate prescribed in the JNPT SOR is Rs.2550/-. So, should the TP billing be based on Rs.1275/- or be based on Rs.1275/- for the foreign vessel and Rs.637.50 for coastal barge.
- 2.2 With reference to the above, the JNPT in its letter dated 3 March 2008 has made the following main submissions:

- (i). No separate rate is prescribed for handling coastal transhipment containers.
- (ii). The charges applicable for transhipment containers are 50% of the normal handling charges.
- (iii). The JNPT levies Rs.2550/- per TEU as per Clause 3.3.1(D) of Chapter 3 of the JNPT Scale of Rates for the same service.
- 2.3. Since the MSPL is not in agreement with the views of JNPT, the JNPT has requested this Authority to clarify the charges actually leviable by the port for a transhipment container vis-à-vis the provisions of its Scale of Rates.
- 3.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the reference from the JNPT along with the enclosures was forwarded to the concerned users/ user organizations for their comments.
- 3.2. The comments received from Mumbai and Nhava-Sheva Ship-Agents' Association (MANSA) and Container Shipping Lines Association (India) [CSLA] were forwarded to JNPT as feedback information. We have not received the response of JNPT till the finalization of this case.
- 4. A joint hearing in this case was filed on 27 November 2009 in the office of this Authority. The JNPT and the users made their submissions.
- 5. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.
- 6. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:
 - (i). In compliance of a policy direction issued by the Government of India under Section 111 of the MPT Act, 1963, to prescribe concessional rates for coastal cargo / containers / vessel related charges levied at all major port trusts and the private terminal operators thereat, this Authority amended the Scale of Rates of all major port trusts and private terminal operators to insert the policy direction of the Government in the form of general conditionalities with effect from 1 February 2005 vide Order No. TAMP/4/2004-Genl. Dated 10 January 2005. The general conditionalities were introduced to prescribe concessional coastal cargo / container / vessel related charges in line with policy direction of the Government in the Scale of Rates of the respective ports / terminals.
 - (ii). Clause 4.3. of the tariff guidelines of March 2005 stipulates prescription of concessional tariff for coastal containers not exceeding 60% of the rates of normal container related charges.
 - (iii). Clause 5.5.1 of the tariff guidelines stipulates that the handling charges for transhipment containers shall be concessional. Such charges shall be calculated with reference to the applicable handling charges subject to the concession specified in Clause 4.3 for coastal containers.
 - (iv). The Scale of Rates of JNPT was last revised in September 2006 vide Order dated 28 September 2006 in Case No. TAMP/48/2005-JNPT. Clause 1.2 (vi)(b) prescribed in Chapter 1 of the existing Scale of Rates of JNPT provides for levy of coastal rates at 60% of the rates prescribed for handling foreign containers.
 - (v). In terms of Note 4 of Section 3.3.3 prescribed in the Scale of Rates of JNPT, a container from foreign port landing at the JNPT for subsequent transhipment to an Indian Port on a coastal voyage or vice versa would be charged at 50% of the transhipment charges prescribed for foreign going vessels and 50% of that prescribed for coastal category.
 - (vi). The prescription made in Section 3.3.1 of the existing Scale of Rates of JNPT with regard to levy of charges for handling transhipment containers is given below:

SI. No.	Description	Rate per TEU (in R	s.) Foreign Containei
1.	1 - 3000 TEUs	Loaded	Empty
2.	3001 - 6000 TEUS	2550	2210
3.	6001 - 9000 TEUS	2380	2040
4.	Thereafter	2210	1870
	L. DUITO!	2040	1700

As can be seen from the above, rates for coastal transhipment containers are not specifically included in the above table and notified.

- (vii). A Scale of Rate is not a document giving some set of rates alone for the services provided. It also contains the conditionalities governing application of rates. Therefore, the Scale of Rates of JNPT is to be seen in totality to decide on the applicable tariff. Harmonious reading of Clause 1.2 (vi) (b) of Chapter 1 and note position that the coastal rates for transhipment containers is applicable and transhipment containers is for foreign containers alone as seen from the header given in the table. If the intention is not allowing any concession to coastal transhipment, which in any case would have been contrary to the Government policy, there would be no need to prescribe Note 4 under Section 3.3.3. detailing the charging basis when transhipment involves foreign as well as coastal legs.
- (viii). Incidentally, in the Scale of Rates of other two private container terminals at the JNPT namely, NSICT and GTIPL, the coastal rates for transhipment containers have been prescribed at 60% of the rates prescribed for foreign transhipment containers. It is relevant here to mention that the NSICT and GTIPL initially adopted the tariff structure of JNPT and the existing tariff structure of NSICT and GTIPL draws the genesis from the same tariff structure of JNPT. The Scale of Rates of both NSICT and GTIPL specifically carry a separate provision relating to prescribed for foreign transhipment containers.
- (ix). Following Clause 1.2 (vi)(b) of the Scale of Rates of JNPT mentioned earlier and keeping in view Clause 5.5.1 of the tariff guidelines of 2005 which, inter alia, stipulates prescription of handling charges for transhipment coastal containers, the schedule under the existing sub-section D in Section 3.3.1 is to be taken to read as follows:

Handling of transhipment containers:

SI. No.	Description	Rate per TEU (in Rs.)			
		Foreign Container		Coastal Container	
1	1 2000 TELL	Loaded	Empty	Loaded	Empty
2	1-3000 TEUs	2550	2210	1530	1326
<u> </u>	3001-6000 TEUs	2380	2040	1428	1224
3.	6001-9000 TEUs	2210	1870	1326	1122
4.	Thereafter	2040	1700	1224	1020

- (x). By virtue of the existing Note 4 of Section 3.3.3., a container from foreign port landing at the JNPT for subsequent transhipment to an Indian port on a coastal voyage or vice-versa would be charged at 50% of the transhipment charges prescribed for foreign containers and 50% of that prescribed for coastal category.
- 8.1. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority clarifies that the existing Scale of Rates of JNPT already provides for concessional rates for transhipment of coastal containers and also provides for devising applicable provisions in its Scale of Rates.

8.2. This Authority is of the view that a container from a foreign port with declared final destination to any port other than JNPT but handled at JNPT en route will only be eligible for transhipment rates. To put it in different words, a foreign container which is originally destined to JNPT and subsequently re-consigned to another Indian port from JNPT shall not be eligible for transhipment rates. In such cases of re-consignment from JNPT to another Indian Port, the normal coastal rate for its coastal voyage between JNPT and another port shall be applicable. As the issue involved touches upon the coastal policy of the Government, the Ministry of Shipping is being appraised of the interpretation of this Authority recorded in this sub-paragraph.

RANI JADHAV, Chairperson [ADVT III/4/143/09-Exty.]